

प्रेषक,

एस.के. मुद्दू
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 3-5-2010

विषय:- ग्राम महेशपुरा, तहसील काशीपुर, जिला उधमसिंहनगर में क्षेत्राधिकारी, काशीपुर के कार्यालय/आवास हेतु कुल 0.325 है० भूमि, गृह विभाग, उत्तराखण्ड को निशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-615/सात/स०भू०अ०/2009, दि. 3.12.2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, ग्राम महेशपुरा, तहसील काशीपुर, जिला उधमसिंहनगर में क्षेत्राधिकारी, काशीपुर के कार्यालय/आवास हेतु कुल 0.325 है० भूमि, जो नॉन.जेड.ए. के खाता सं०-117 पर नाम मालिकान के रूप में कोलोनाइजेशन विभाग, श्रेणी 15(2) आबादी कोलोनाइजेशन का नाम खसरा सं०-622 के अधीन दर्ज माल कागजात है, को जिलाधिकारी उधमसिंहनगर की संस्तुति, एवं वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15-02-02 के प्राविधानों के अन्तर्गत, गृह विभाग, उत्तराखण्ड को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 1- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- 2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।
- 3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
- 5- जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

- 6- जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
- 7- प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत गैर वानिकी कार्यों के लिए नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

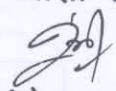
भवदीय,

(एस.के. मुट्ठू)
प्रमुख सचिव।

पृ०प०संख्या- /समदिनांकित/ 2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3- आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
- 4- निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय।✓
- 5- प्रभारी मीडिया केन्द्र सचिवालय।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।